



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 632) पटना, बृहस्पतिवार, 18 जून 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

18 जून 2026

सं० 7/स्था0-04-16/2026-10900/सा0प्र0—भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) यह नियमावली “बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट-‘ग’ के उप नियम-8 में अंकित विषय “द इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872”, “द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973” तथा “इंडियन पेनल कोड, 1860” का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के परिशिष्ट-‘ग’ के उप नियम-8 में अंकित विषय “द इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872”, “द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973” तथा “इंडियन पेनल कोड, 1860 को क्रमशः निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जायेंगे:—

- (i) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बी0एस0ए0)।
- (ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी0एन0एस0एस0)।
- (iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बी0एन0एस0)।

3. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट-‘ग’ के उप नियम-9 में अंकित विषय “द इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872”, “द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973” तथा “इंडियन पेनल कोड, 1860” का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के परिशिष्ट-‘ग’ के उप नियम-9 में अंकित विषय “द इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872”, “द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973” तथा “इंडियन पेनल कोड, 1860” को क्रमशः निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जायेंगे:—

- (i) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बी०एस०ए०)।
- (ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी०एन०एस०एस०)।
- (iii) भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बी०एन०एस०)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 18th June 2026

No. 7/Astha.-04-16/2026-10900/GAD—In exercise of the powers conferred by Article 233 of the Constitution of India read with the proviso to Article 309, the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following amendment in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) These rules may be called "**The Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2026**".
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of the Government of Bihar.

2. Substitution of subject “The Indian Evidence Act, 1872”, “The Code of Criminal Procedure, 1973” and “Indian Penal Code, 1860” mentioned in sub rule-8 of Appendix ‘C’ of the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time).—The subject “The Indian Evidence Act, 1872”, “The Code of Criminal Procedure, 1973” and “Indian Penal Code, 1860” mentioned in sub rule-8 of Appendix ‘C’ of the said Rules shall be substituted by the following respectively:-

- (i) **The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA).**
- (ii) **The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS).**
- (iii) **The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS).**

3. *Substitution of subject “The Indian Evidence Act, 1872”, “The Code of Criminal Procedure, 1973” and “Indian Penal Code, 1860” mentioned in sub rule-9 of Appendix ‘C’ of the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time).—*The subject “The Indian Evidence Act, 1872”, “The Code of Criminal Procedure, 1973” and “Indian Penal Code, 1860” mentioned in sub rule-9 of Appendix ‘C’ of the said Rules shall be substituted by the following respectively:-

- (i) The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA).
- (ii) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS).
- (iii) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS).

By the order of Governor of Bihar,
Rajnish Kumar,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 632-571+200—डी०टी०पी०
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>